

**Amendment to National Highways Act**

804. SHRI GHUFRAN AZAM Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state.

(a) whether Government propose to amend the National Highways Act,

(b) if so, the reasons therefor,

(c) whether it is a fact that the condition of National Highways throughout the country is in a very bad shape,

(d) if so, how much expenditure has been incurred by the Central Government to repair the National Highways during the past three years, year-wise, and

(e) what further steps Government propose to contemplate to maintain National Highways?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b) Yes, Sir. In order to mobilise additional resources

(c) and (d) National Highways in the country are generally in a traffic worthy condition and improvement works are undertaken keeping in view the existing condition, traffic intensity, inter-se priority on an All-India basis and availability of funds. Expenditure incurred on maintenance of various National Highways during the past three years is as under:—

1987-88	Rs 10,915 76 lacs
1988-89	Rs. 14,634 61 lacs
1989-90	Rs 15,796 29 lacs

(e) Introduction of computer-aided Pavement Management System for optimal utilisation of available scarce resources

नेपाल में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा अड़्डे लाये जाना

805. श्री राम जेठमलानी :

श्री ललराम सिंह यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान इन

समाचारों की और दिलाया गया है कि कश्मीर के अनेक पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए नेपाल में अपने अड़्डे बना रहे हैं,

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ बात की है ;

(ग) क्या नेपाल में इन अड़्डों से निपटने के लिए सयुक्त कार्रवाई करने के संबंध में दोनों देशों में कोई समझौता है ; और

(घ) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हा ।

(ख) से (घ) नेपाल और भारत की सरकारों के बीच समुचित स्तरों पर इसके संबंध में विचार-विमर्श होता रहा है । 25-26 नवम्बर, 1990 की हाल की अपनी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने कहा था कि अगर नेपाल राज्य में किसी कश्मीरी अथवा पजाबी आतंकवादी को शरण देने का कोई मामला उनकी जानकारी में आता है तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे । तथापि इस प्रकार के मामलों से संबंध कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है ।

फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेदभाव

806. श्री राम जेठमलानी :

डा० जिनेंद्र कुमार जैन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1990 के "द हिन्दू" से "रिटर्न टू द मदरलैंड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है, यदि हाँ तो क्या यह सच है कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों के साथ भेद भावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ; और